



- वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल लोकसभा में वर्ष 2026–27 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी— बजट की प्रति मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत किसानों को 25 करोड़ से ज़्यादा कार्ड वितरित किये गए।
- सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं की प्रतिष्ठता, स्वास्थ्य और समानता सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों को निर्देश जारी किए।
- अखिल भारतीय सिविल सेवा बैडमिन्टन और शतरंज प्रतियोगिता के लिए चयन ट्रायल तीन और चार फरवरी को आयोजित किया जाएगा।



वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल लोकसभा में वर्ष 2026–27 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। लोकसभा के बाद बजट की प्रति राज्यसभा में पेश की जाएगी। संसद में बजट भाषण सम्पन्न होने के बाद बजट की प्रति मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। श्रीमति सीतारामन, बजट के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों के महाविद्यालयों से आए तीस विद्यार्थियों से बातचीत करेंगी। देश के विभिन्न हिस्सों से आए महाविद्यालयों के लगभग तीस विद्यार्थियों को कल लोकसभा गैलरी से केंद्रीय बजट की कार्यवाही देखने का अवसर मिलेगा।



देशभर में किसानों को पच्चीस करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। वर्ष दो हजार पन्द्रह में सरकार ने भूमि में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की थी। पिछले वर्ष जुलाई तक इस योजना के अंतर्गत तिरानब्बे हजार से ज्यादा किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है, खेतों के छह लाख से अधिक अवलोकन कार्यक्रम आयोजित हुए और हजारों जागरुकता कार्यक्रम भी संचालित किए गए। सरकार ने कहा है कि ये उपलब्धियां इस योजना के विस्तार और बढ़ते पैमाने को दर्शाती हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड हर दो वर्ष के अंतराल पर वितरित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से भूमि की भौतिक-रसायन जानकारी और पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में सूचना का प्रसार किया जाता है। मृदा

स्वास्थ्य कार्ड किसानों को फसल आधारित खेती करने और सही मात्रा में उर्वरक तथा रासायनिक तत्वों के इस्तेमाल की जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें जैविक उर्वरक और खाद के सही उपयोग के तरीके भी शामिल हैं। इसका लक्ष्य किसानों को बेहतर फसल उगाने के निर्णय लेने और लंबे समय तक मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।



नासा ने फ्लोरिडा में प्रतिकूल मौसम के कारण चांद के लिए अपना आर्टेमिस-2 मिशन को स्थगित कर दिया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने 6 फरवरी की निर्धारित अपनी पहले की योजना को बदलकर लॉच तिथि को अब आठ फरवरी कर दिया है। इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले दुर्लभ आर्कटिक प्रकोप से जुड़े ठंड के मौसम और तीव्र हवाओं की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। नासा दो फरवरी को गीले ड्रेस रिहर्सल करेगा। इसके बाद अंतिम लॉच तिथि की पुष्टि की जाएगी। आर्टेमिस-2 दस दिवसीय मानव मिशन है। इस मिशन में ओरियन अंतरिक्ष यान और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए चांद के आसपास चार अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। इस मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर नहीं उतारा जाएगा।



सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य संविधान के तहत मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मासिक चक्र जीने के अधिकार और निजता के अधिकार का आंतरिक अंग है। सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों और महिलाओं की प्रतिष्ठता, स्वास्थ्य और समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों और विद्यालयों को कई निर्देश दिये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए निशुल्क बायोडिग्रेडेबल सैनेटरी नेपकिन निशुल्क उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने एक याचिका पर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायालय ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि प्रत्येक स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय हों। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी और निजी सभी तरह के शिक्षण संस्थाओं के लिए इस आदेश का पालन करना अनिवार्य है।



विरासत और तकनीक आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय ने उच्च गुणवत्ता वाले वर्चुअल रियलिटी वृत्तचित्रों की एक श्रृंखला शुरू की है। यह पर्यटकों को द्वीप समूह का इमर्सिव, एरियल और 360-डिग्री अनुभव प्रदान करेगा। ये वृत्तचित्र निकोबार द्वीप समूह, विशेष रूप से कामोर्टा और ननकौड़ी हार्बर के सांस्कृतिक और नृवंशविज्ञान महत्व को जीवंत रूप से दर्शाते हैं। इसमें पारंपरिक खेल उत्सव पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। पर्यटकों और आम जनता की सुविधा के लिए, इन वृत्तचित्रों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया गया है। इन्हें देखने के लिए एक विशेष रूप से डिजाइन की गई चलती-फिरती बस में 'मोबाइल वीआर थिएटर' बनाया गया है।



कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं खेल बोर्ड, दिल्ली सरकार के सहयोग से पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए अखिल भारतीय सिविल सेवा बैडमिन्टन और शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों के चयन हेतु खेल एवं युवा मामले विभाग की ओर से तीन फरवरी को सुबह नौ बजे से नेताजी खेल परिसर में बैडमिन्टन और चार फरवरी को सुबह साढ़े आठ बजे से टीचर्स होम में चयन ट्रायल आयोजित की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी, सशस्त्र बल, पुलिस संगठनों में कार्यरत कर्मचारी, राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी, क्षेत्रीय खेल बोर्ड की टीम और खेल अधिकारी या प्रशिक्षक भाग ले सकते हैं। चयन परीक्षण में भाग लेने वाले सरकारी कर्मियों को अपने संबंधित विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र और अनापत्ति प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य है।



स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने आज बताया कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा- स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) राउंड 3 काउंसलिंग प्रक्रिया फिर शुरू हो चुकी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डीजीएचएस ने बताया कि काउंसलिंग प्रक्रिया नए पंजीकरणों की सुविधा के साथ फिर शुरू हुई है। पात्र उम्मीदवारों को और अवसर प्रदान करते हुए अतिरिक्त सीटें भी शामिल की गई हैं। पात्र उम्मीदवारों को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने और तदनुसार विकल्प चुनने की सलाह दी गई है। अधिक जानकारी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।



भारतीय जनता पार्टी, की ओर से कल शाम चार बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय बजट-2026 पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी मीडिया को संबोधित करेंगे। इस दौरान "केंद्रीय बजट-2026" की प्रमुख घोषणाएं और द्वीप समूह के विकास पर इसके प्रभाव पर चर्चा की जाएगी।



सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी, जन-सुलभ और जवाबदेह बनाने के लिए उम्मीद पोर्टल पर सर्वेक्षण मॉड्यूल तथा वक्फ संपत्ति पट्टा मॉड्यूल शुरू किया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने कहा है कि सर्वेक्षण मॉड्यूल, पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण से संबंधित जानकारी को एकत्र करने, प्रबंधित करने और अद्यतन के लिए डिजिटल ढांचा प्रदान करता है। वक्फ संपत्ति पट्टा प्रबंधन मॉड्यूल को वक्फ संपत्तियों की पट्टा संबंधी जानकारी के संपूर्ण प्रबंधन को सुगम बनाने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया है।

